

प्रेषक,

डा० आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: ०६ जनवरी, 2022

विषय—कनोस्सियन फाउण्डेशन इण्डिया कुकरौत फाउण्डेशन इण्डिया कुकरैल, फरीदनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश को शिक्षण संस्थान हेतु कुल—0.54 है० (27 नाली) भूमि क्य की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—1056/पांच—स्टाम्प अनु०/2020—21, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 तथा पत्र संख्या—2653/पांच—स्टाम्प अनु०—2020—21, दिनांक 19 फरवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कनोस्सियन फाउण्डेशन इण्डिया कुकरौत फाउण्डेशन इण्डिया कुकरैल, फरीदनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश को शिक्षण संस्थान खोले जाने हेतु ग्राम ऐरोली के ज०वि०ख०खा० संख्या—42 बसरह नम्बर 459 मे से कुल—0.54 है० (27 नाली) भूमि दानस्वरूप प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2— उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कनोस्सियन फाउण्डेशन इण्डिया कुकरौत फाउण्डेशन इण्डिया कुकरैल, फरीदनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश को शिक्षण संस्थान खोले जाने हेतु ग्राम ऐरोली के ज०वि०ख०खा० संख्या—42 बसरह नम्बर 459 मे से कुल—0.54 है० (27 नाली) भूमि क्य की अनुमति शिक्षा विभाग की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा—154(4)(3)(क)(I)(III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलौक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2— केता द्वारा क्य की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी शिक्षण संस्थान के प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होंगे।

मेरी
अभिलिखित
दस्तावेज़

- 3— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 4— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6— संस्था द्वारा क्य की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र शिक्षण संस्थान खोले जाने हेतु ही किया जायेगा।
- 7— स्थल पर निर्माण प्रचलित उप विधि के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।
- 8— शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान सीड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करना आवश्यक होगा।
- 9— जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्य की जाय।
- 10— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू—उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 11— किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो सके इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 12— भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्य की अनुमति प्रदान की गयी है।
- 13— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।
- 14— सम्बन्धित संस्था द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 15— जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 16— क्य की जा रही भूमि के विक्रय अभिलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।
- 17— संस्था के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र दिया जायेगा।

१४.

- 18— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 3— कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या-५४ (१) / XVIII(II) / 2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
- 3— आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 4— निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— निर्मला माटिंग, निदेशक, परिषद (बोर्ड), फरीदनगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7— प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गीता शरद)
अनु सचिव।